भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1478

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

6 अग्रहायण, 1941 (शक)

भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना

1478. श्री शान्तनु ठाकुर:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इसके आरंभ से सरकार द्वारा आवंटित निधि का वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के लागू होते ही युवाओं हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसी अवधि के दौरान इस योजना के तहत सृजित रोजगार की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(ग)** : ग्रामीण क्षेत्रों (मेट्रो स्थानों को छोड़कर) छोटे शहरों और नगरों में रोजगार के अवसर पैदा करने और आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करने के लिए सरकार ने 28 दिसम्बर, 2015 को इंडिया बीपीओ प्रोत्साहन नामक एक योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को प्रोत्साहन, स्थानीय उद्यमियों इत्यादि को प्रोत्साहन जैसे विशेष प्रोत्साहनों के साथ पूंजीगत और प्रचालन संबंधी व्यय के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधियन के रूप में प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 48,300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। वित्तीय सहायता के संवितरण प्रत्यक्ष तौर पर इसके उद्देश्य यानि यूनिटों द्वारा रोजगार सृजन से जुड़े हुए हैं। इन योजनाओं के प्रारंभ से ही 243 यूनिटों ने देशभर के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना के तहत शामिल होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर) में स्थित कुल 47,244 सीटों के लिए बीपीओ/आईटीईएस प्रचालन प्रारंभ किए हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 33,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आईबीपीएस की अवधि दिनांक 31.3.2019 तक थी। इस योजना के अंतर्गत प्रचालन शुरू करने वाली बीपीओ/आईटीएस यूनिटों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

******

अनुबंध

बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों का विवरण आईबीपीएस के तहत शुरू हुआ				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**यूनिटें**	**सीट***	**रोजगार**
1	आंध्र प्रदेश	45	13584	8749
2	बिहार	12	2300	1095
3	चंडीगढ़ यू.टी.	1	100	58
4	छत्तीसगढ़	4	400	194
5	गुजरात	1	100	10
6	हरियाणा	3	300	151
7	हिमाचल प्रदेश	3	250	144
8	जम्मू और कश्मीर	8	400	559
9	झारखंड	20	2950	1752
10	कर्नाटक	11	2400	1353
11	केरल	3	400	205
12	मध्य प्रदेश	6	1300	1155
13	महाराष्ट्र	16	3445	2059
14	ओडिशा	21	2232	1894
15	पुदुचेरी यू.टी.	1	100	105
16	पंजाब	10	2600	3481
17	राजस्थान	3	400	579
18	तमिलनाडु	47	6865	8035
19	तेलंगाना	3	2398	210
20	उत्तर प्रदेश	13	3320	902
21	उत्तराखंड	6	500	295
22	पश्चिम बंगाल	6	900	182
कुल		**243**	**47,244**	**33,167**

* प्रत्येक राज्य के लिए बजट का आवंटन आवंटित सीटों के अनुसार है।